

नगरीकरण के कारण दो दशकों में तेजी से समाप्त होता लखनऊ के गाँवों का अस्तित्व

सारांश

बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण शहरों से लगे हुए गाँव तेजी से समाप्त हो रहे हैं जिससे गाँवों का अस्तित्व आज खतरे में पड़ गया है लखनऊ शहर में जहाँ दो दशक (बीस वर्ष) पहले 959 गांव थे वही वर्तमान में ग्रामों की संख्या घटकर 819 ही रह गयी है। जिसका कारण नगरों पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव के साथ ही भूमाफियाओं द्वारा अवैद्य कब्जा भी है।

मुख्य शब्द : गाँव, नगरीकरण, लखनऊ।

प्रस्तावना

गाँव का साफ-सुधरा हरा-भरा शुद्ध वातावरण, गाँव की सोधी मिट्टी की खुशबू नगरीकरण या शहरी विस्तार के कारण तेजी से समाप्त होते गाँव एक नई कहानी बयां कर रहे हैं। जिसके कारण बहुत से हैं जहाँ एक ओर गाँव एक-एक करके शहरी क्षेत्र से जुड़ते जा रहे हैं वही कुछ गाँव टाउन ऐरिया से जुड़ गये, वही बहुत से गाँवों को एलडीए ने अधिग्रहण कर लिया तो कुछ गाँवों की जर्मीनों पर बड़-बड़े भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया।

कुल मिलाकर अब स्थिति यह है कि लखनऊ में जहाँ बीस वर्ष पहले 959 गाँव थे वे वर्तमान में अब एक सरकारी ऑकड़े के मुताबिक 819 गांव शेष रह गया है इन बीस वर्षों में लखनऊ के करीब 140 गाँवों का अस्तित्व समाप्त हो गया।

गाँवों के देश कहे जाने वाले भारत में भी नगरीकरण की दर अत्यधिक तीव्र गति से वृद्धि की ओर अग्रसर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 31.16 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में यह दर राष्ट्रीय ऑकड़ों की तुलना में काफी मंद रही है। 2011 की अंतिम जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कुल 199812340 जनसंख्या में से ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या क्रमशः 77.70 और 22.30 प्रतिशत हैं।

एक अनुमान के अनुसार, विगत सौ वर्षों की अवधि में गाँवों की जनसंख्या में लगभग 3.5 गुना वृद्धि हुई है, जब कि नगरीय जनसंख्या में 15 गुना से भी की अधिक की वृद्धि हुई है।

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गाँवों के अध्ययन पर अधारित है यह अध्ययन सन् 2008 से 2012 समय समय पर किया गया तथा वर्तमान के परिपेक्ष्य से भी संबंधित है अध्ययन में क्षेत्र कार्य, घर-घर सर्वे तथा असहभागी अवलोकन की पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन का प्रारूप विवणात्मक है।

प्रस्तुत शोध में ग्रामीण समाज का नगरीकरण पर प्रभाव का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में यह स्पष्ट होता है कि गाँव पर नगरीकरण का प्रभाव एक महत्वपूर्ण परिघटना है।

गाँव के लोग नगरीय जीवनशैली व संस्कृति से आकर्षित होकर उसे अपना रहे हैं साथ ही साथ वे अपनी मूल्य परम्पराओं व विचारों को भी महत्व देते हैं परन्तु पहले की तरह उनमें उतनी कठोरता नहीं रही है। नगरीकरण के प्रभाव से लोगों में लचीले दृष्टिकोण का उदय हुआ है।

अध्ययन के दौरान ये ज्ञात हुआ कि पिछले दो दशकों में लखनऊ के करीब डेढ़ सौ गाँवों का अस्तित्व मिट गया। लखनऊ जिले में गाँवों की संख्या तेजी से घट रही है। एक सरकारी ऑकड़े के मुताबिक वर्ष 1981 से अब तक कुल एक सौ पैतीस गाँव समाप्त हो चुके हैं। मौजूदा समय में लखनऊ जनपद में कुल आठ सौ उन्नीस गाँव ही शेष बचे हैं।

जब कि 1981 में लखनऊ जनपद में कुल नौ सौ उनसठ गाँव थे। जिनमें से एक हजार से पन्द्रह सौ आबादी वाले 228 गाँव 500 से 1000 की जनसंख्या पर 313 गाँव तथा 5000 और इससे अधिक आबादी वाले आंठ गाँव थे। वही वर्ष 1991 में इनकी संख्या घटकर आठ सौ चौबीस हो गयी। यानी इन दस वर्षों में एक सौ पैतीस गाँवों का वजूद मिट गया।

वर्ष 2001 में इनकी संख्या और घटी यह तब आठ सौ बाइस गाँव हो गयी। इनमें एक हजार से अधिक आबादी वाले गाँवों की संख्या तो बढ़ी लेकिन दो सौ से कम और इससे अधिक आबादी वाले गाँव खत्म हो गये।

अब वर्तमान में पांच हजार से अधिक आबादी वाले चौबीस गाँव, दो हजार से पांच हजार तक की जनसंख्या वाले एक सौ सात गाँव तथा एक हजार की जनसंख्या के एक सौ सात गाँव तथा एक हजार से पन्द्रह सौ तक की आबादी वाले एक सौ इकहत्तर गाँव रह गये। लेकिन कम आबादी वाले गाँव खत्म हो गये।

इस संबंध में जानकारों का कहना है कि पहले चिनहट, खुर्मनगर, भरवारा, कल्याणपुर तथा सरोजनी नगर आदि इलाके ग्रामीण क्षेत्र में ही आते थे लेकिन एक-एक करके ये गाँव शहरी क्षेत्र से जुड़ गये। इस कारण इनका असतित्व समाप्त हो गया। वही कुछ गाँव टाउन एरिया से जुड़ गये। चिनहट के मल्हौर, छोटा भरवारा, तिवारीपुर, खरगापुर, लवलाई समेत आधा दर्जन से ज्यादा गाँवों पर एलडीए अधिग्रहण कर रहा है। इससे शीघ्र ही ये गाँव भी खत्म हो जायेंगे। कमोवेश यही स्थिति अन्य ब्लाकों के भी गाँवों कि बनी है जो तेजी से शहरी सीमा में शामिल हो रहे हैं।

वर्ष 2011 की एक सरकारी आंकड़े के अनुसार लखनऊ जनपद के गाँवों की संख्या वर्तमान में घटकर आठ सौ उन्नीस ही रह गयी है।

यही स्थिति गाँव से जुड़े हुए जल के प्राकृतिक स्त्रोंतों की भी है एक सर्वे के मुताबिक राजधानी में तालाब-पोखरों, कुये, झीलों का सूखना जारी हैं यह भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। 13 से अधिक तालाब, झील, कुये दर्जनों पोखरे कुल मिलाकर सात हजार जल के स्त्रोत पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। वही सूख चुके 2542 पोखर-तालाब अवैध कब्जेदारी के पाट में

फैसे हैं। दरसल अवैध कब्जे के कारण इनका वज्रुद खत्म होता जा रहा है।

कुल मिलाकर गाँवों की घटती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए प्रयास करना होगा जिससे हम गाँवों की खूबसूरती की विरासत को अपनी आने वाली पीढ़ियों का सोप सके।

उद्देश्य

गाँवों की घटती हुई संख्या तथा उससे भविष्य में होने वाली समस्याओं से अवगत कराने का एक प्रयास।

निष्कर्ष

जनसंख्या दबाव के कारण, बढ़ते हुए नगरीकरण के परिणामस्वरूप गाँवों में मिलने वाला शुद्ध वातावरण तथा गांव के प्राकृतिक स्त्रोत प्रभावित हो रहा हैं गाँवों की संख्या तीव्र गति से घट रही हैं। जब कि हमें अपने गाँव की धरोहर को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सजो कर रखना हैं नहीं तो वे गाँव की सोधी मिट्टी की खुशबू से वंचित रह जायेंगे और वास्तव में गाँव के सुख से भी गांव का किस्सा सिर्फ किस्से-कहानियों, फिल्मों में दर्शाये गये दृश्यों तक ही सीमित रह जायेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ई० बी० बर्गल; अर्बन सोशियोलोजी : पेज न० ३, गाडेल ब्रीज; अर्बनाइजेशन इन न्यूली डेवलपिंग कन्ट्रीज : पेज न० ३, दूबे, एस०सी०, इण्डियन विपेज, एलाइड पब्लिशर, बाम्बे: 1967,
2. देसाई, ए०आ००, रुरल सोशियोलोजी इन इन्डिया, पापुलर प्रकाशन बाम्बे: 1969, योजना मार्च-2003 प्रकाश चन्द्र शुक्ला, योजना मई- 2003 अजय प्रताप सिंह, दैनिक जागरण अगस्त-2007 रमेश दूबे, दैनिक जागरण 22 जनवरी ऋतु सिंह, भारतीय जनगणना रिपोर्ट-2001, 2011, 8 मई 2016 अमर उजाला सेव वाटर अभियान लेख।